भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 173
सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

भारत में युवा बेरोजगारी दर

173. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की इस रिपोर्ट से सहमत है कि भारत में युवा बेरोजगारी दर अब वैश्विक स्तर से अधिक है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले दस वर्षों के दौरान शिक्षित युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियों का सृजन नहीं कर पाई है;

(ग) क्या तथाकथित गिग जॉब्स में वृद्धि अथवा अस्थायी और कम वेतन वाले रोजगार भारत में रोजगार की स्थिति के लिए चिंताजनक हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मुद्दों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): मानव विकास संस्थान (आईएचडी) - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की भारत रोजगार रिपोर्ट, 2024 में उल्लेख किया गया है कि आईएलओ की ग्लोबल रिपोर्ट ट्रेंड्स फॉर यूथ, 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया भर में युवा बेरोजगारी दर 15.6 प्रतिशत थी। इसके साथ, आईएलओ द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स, 2024 के अनुसार, वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर, युवा बेरोजगारी दर 13.3 प्रतिशत थी। वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-2018 से आयोजित किए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) भारत में रोजगार/बेरोजगारी संकेतक का आधिकारिक डेटा स्रोत है। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष के जून माह तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 में सामान्य स्थिति के आधार पर देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 10.2% थी जो वैश्विक स्तर से कम है। इसके साथ-साथ, रोजगार को दर्शाने वाले युवाओं के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 31.4% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का वेतन-सूची डेटा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1.3 करोड़ से अधिक अभिदाता ईपीएफओ में शामिल हुए। इसके साथ-साथ, सितंबर 2017 से अगस्त, 2024 के दौरान, 7.03 करोड़ से अधिक अभिदाता ईपीएफओ में शामिल हुए हैं, जो रोजगार के औपचारिकीकरण में वृद्धि का संकेत देता है।

सभी श्रम बल संकेतक देश में बेहतर रोजगार परिदृश्य का प्रमाण दे रहे हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि कार्यान्वित कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programm**es** पर देखा जा सकता है।

*****